राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5245/2022

अभय सिंह पुत्र श्री बांके सिंह, आयु लगभग 61 वर्ष, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, निवासी ग्राम सोनू, जिला जैसलमेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जोधपुर।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जोधपुर संभाग, जोधपुर।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री चिराग खत्री
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री श्रवण कुमार

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

22/04/2024

1. इस याचिका के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी आदि के संबंध में उसकी अन्य देय राशि ब्याज सहित वितरित करने का आदेश देने के लिए उचित निर्देश मांगा गया है।

2. संक्षेप में प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 31.07.2021 को वरिष्ठ शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं थी, फिर भी उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। 07.03.2022 (अनुलग्नक 4) दिनांकित एक कानूनी नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (पेंशन अधिकारी) की ओर से दायर प्रतिक्रिया में लिया गया रुख यह है कि वे सिद्धांत रूप में पेंशन लाभ वितरित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में कुछ कमियां थीं। इसलिए, फाइल संबंधित विभाग को भेज दी गई थी और विभाग को इसे ठीक करना है।

4. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से दायर जवाब में यह पक्ष रखा गया है कि याचिकाकर्ता को पेंशन विभाग द्वारा जारी पीपीओ संख्या 1167493 के तहत 100% अनंतिम पेंशन दी गई है और 50% अनंतिम ग्रेच्युटी भी स्वीकृत की गई है। विवाद यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1990 में अपनी अस्थायी नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ का दावा कर रहा है, जबकि याचिकाकर्ता की मूल नियुक्ति वर्ष 1992 में हुई थी।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

6. यह पता चलता है कि यहां एक बहुत छोटा विवाद यह है कि क्या विभाग याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद 10 साल से अधिक समय तक प्रशासनिक निर्णय पर विचार कर सकता है?

7. वस्तुतः प्रश्न का उत्तर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 12 के आलोक में स्वतः निहित है, जो नीचे उद्धृत है:-

"12. अर्हक सेवा का प्रारंभ

(क) प्रतिकर उपदान को छोड़कर, सरकारी सेवक की सेवा अठारह वर्ष की आयु पूरी करने तक अर्हक नहीं होती है।

(ख) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, सरकारी सेवक की अर्हक सेवा उस तिथि से प्रारंभ होगी, जिस दिन वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर उसे पहली बार मौलिक रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया है।"

8. उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पेंशन लाभ के उद्देश्य से, नियमितीकरण की तिथि पहली नियुक्ति की तिथि से तय की जानी है।

9. प्रतिवादी केवल इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को रोक नहीं सकते क्योंकि मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, इस आधार पर कि प्रशासनिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। नियमों के नियम 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा लाभ देते समय प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10. मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि इस संबंध में, हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शीला देवी, 2023(5) सुप्रीम 323 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर स्थिति अन्यथा भी अधिक सुसंगत नहीं है, जिसमें यह माना गया है कि पेंशन के उद्देश्य से संविदा कर्मचारी के रूप में भी पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रासंगिक निम्नलिखित है:-

"9. विद्वान महाधिवक्ता अपनी व्याख्या में सही हैं, क्योंकि नियम 2(जी) को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि संविदा कर्मचारियों को पेंशन नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम अपने आरंभिक शब्दों में ही पेंशन नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुप्रयोग को बचाता है: "इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के अलावा।" यदि नियम 2 के आरंभिक वाक्यांश को इस संदर्भ में समझा जाए, तो राज्य द्वारा नियम 17 की किसी भी व्याख्या से इस तरह के मूल प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे। नियम 17 को अनिवार्य रूप से उस स्थिति को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था, जहां संविदा आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को बाद में नियमित

किया गया था। केवल पेंशन के प्रयोजनों के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

11. उपर्युक्त आधार पर, रिट याचिका को सभी परिणामों के साथ स्वीकार किया जाता है।

12. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को बकाया सेवानिवृत्ति लाभ लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित जारी करें।

13. आज से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाए।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।